गन्ना किसानों को ₹4,050 करोड़ की चाशनी

सी दूसरी कोई फसल नहीं है, जो किसी राज्य की राजनीतिं से इतने करीब से जुड़ी हो, जितनी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सियासत में गन्ने की अहमियत है। यही वजह है कि वेस्टर्न यूपी के शुगर बेल्ट में मौजूद कैराना लोकसभा सीट के उप चुनाव में संयुक्त विपक्ष के हाथों बीजेपी के हारने के बाद मोदी सरकार ने शुगर इंडस्ट्री के लिए पैकेज का ऐलान किया।

शुगर इंडस्ट्री रिकॉर्ड उत्पादन और कीमतों में गिरावट की स्थिति का सामना कर रही है, वहीं किसानों के 22000 करोड़ रुपये चीनी मिलों पर बकाया हैं। ऐसे में राहत पैकेज के राजनीतिक मतलब निकाले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र देश में दो बड़े गन्ना उत्पादक राज्य हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से भी ये दो बड़े राज्य हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 128 इन दो राज्यों में हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2019 के चुनाव में इन राज्यों में पार्टी का धमाकेदार प्रदर्शन दोहराना चाहते हैं। शुगर इंडस्ट्री के लिए सरकारी पैकेज का ऐलान इस दिशा में एक छोटा कदम है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें (महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन के साथ) हैं।

यूपी में गन्ना उत्पादन में उछाल की एक वजह इस फसल की एक नई वेरायटी भी है। मेरठ में भोला गांव के 35 साल के किसान मुकेश कुमार ने नई किस्म Co 0238 की रोपाई की थी। उनका कहना है कि उन्होंने इस किस्म को अपनाने में देर कर दी। मेरठ, मुजफ्फरनगर और कैराना के अधिकतर गन्ना किसान पहले ही इस किस्म को अपना चुके हैं। मुकेश का कहना है कि Co 0238 बेहतर किस्म है, इससे ज्यादा उपज मिलती है। स्थानीय किसानों के बीच Co 0238 'अड़तीस' के नाम से लोकप्रिय है।

उत्तर प्रदेश का यह शुगर बेल्ट देश के कुल गन्ना उत्पादन में लगभग 50 पर्सेंट योगदान देता है। देश के कुल शुगर प्रॉडक्शन यानी रिकवरी रेट में इसका हिस्सा 36 पर्सेंट है। रिकवरी रेट का मतलब गन्ने से बनाई जाने वाली चीनी का प्रतिशत है। कैराना निवासी मुहम्मद हलील ने कहा, 'हम लोगों में से अधिकतर किसान पिछले दो वर्षों से Co 0238 का इस्तेमाल कर रहे हैं।' यूपी के सीतापुर जिले में एक चीनी मिल ने 2015-16 में 12.1% की सबसे ज्यादा शुगर रिकवरी हासिल की थी। माना जा रहा है कि उसके बाद अधिकतर किसानों ने परंपरागत किस्मों से किनारा कर नई किस्म को अपनाना शुरू कर दिया।

कैराना से करीब 100 किलोमीटर दूर दिल्ली के कृषि भवन में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के केंद्रीय सचिव एस के पटनायक गन्ने की इस किस्म की प्रशंसा सतर्कता के साथ करते हैं। उन्होंने कहा, 'गन्ने का रकबा तेजी से बढ़ने में Co 0238 का बड़ा योगदान है। यह वेरायटी खासतौर से उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय हुई है।' उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार में गन्ने के रकबे का करीब 60 पर्सेंट हिस्सा इसी किस्म का है। इससे उत्पादन बहुत बढ़ा है और चीनी की कीमतों में गिरावट में इसका भी योगदान रहा है।

तो क्या Co 0238 की सफलता महज क्रॉप साइंस की कहानी है? ऐसा नहीं है। इसका राजनीतिक असर बहुत बड़ा हो सकता है। यूपी में गन्ने का रकबा बढ़ने से राज्य में गन्ना किसानों की सियासी हैसियत भी बढ़ेगी। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 80 में से 71 सीटों (दो इसकी एक सहयोगी पार्टी को मिली थीं) जीती थीं। इसके चलते वह अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकी। गन्ने और गन्ना किसानों की राजनीति प्रदेश की 25-30 लोकसभा सीटों पर अहमियत रखती है। यूपी का शुगर बेल्ट बागपत, बलरामपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामिल और सीतापुर तक है।

शुगर पॉलिटिक्स

ईटी के रिपोर्टर्स ने मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और कैराना जाकर किसानों की मांगों, मिलों और किसानों के जटिल संबंधों, केंद्र के हालिया राहत पैकेज के संभावित असर और चीनी की राजनीति को समझने की कोशिश की। मई में राष्ट्रीय लोकदल की कैंडिडेट तबस्सुम हसन ने विपक्षी दलों के सहयोग से कैराना में जीत दर्ज की थी। यह सीट पहले बीजेपी के पास थी। इस जीत से उत्साहित आरएलडी ने नारा दिया था, 'जिन्ना हारा, गन्ना जीता।' यह नारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर दक्षिणपंथी संगठनों की राजनीति पर निशाना था। आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का कहना है कि गन्ना किसान उनकी पार्टी की प्रत्याशी के साथ मजबूती से खड़े थे। उन्होंने कहा, 'केंद्र का गन्ना राहत पैकेज हवाहवाई है। यह कैराना के नतीजे और गन्ने पर हमारी पार्टी के नारे के बाद लोगों की निगाहें अपनी ओर खींचने की कोशिश भर है।' चौधरी ने कहा, 'गन्ना किसानों को लगातार चौकस रहना होगा। उन्हें दबाव बनाने के लिए संगठित रहना होगा।' केंद्रीय मंत्री और यूपी के बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने हालांकि यह बात खारिज कर दी कि इस उप चुनाव में गन्ना किसान एकजुट होकर उनकी पार्टी के खिलाफ चले गए थे। नकवी ने कहा, 'कैराना उप चुनाव में हमारी हार का गन्ने से कोई लेनादेना नहीं है। विपक्षी दल एकजुट हो गए थे और वोट ट्रांसफर हुआ था। 2019 के लिए हमारे पास नई रणनीति होगी।' केंद्र सरकार ने मार्च में शुगर पर 20 पर्सेंट कस्टम्स ड्यूटी हटा दी थी ताकि 20 लाख टन चीनी 2017-18 में निर्यात कर अगले सीजन से पहले कुछ सरप्लस स्टॉक क्लियर किया जा सके। हालांकि इंडस्ट्री मांग कर रही है कि यह लिमिट बढ़ाकर 80 लाख टन की जाए। सरकार ने मई में किसानों को हर 100 किलो गन्ने पर 5.5 रुपये की प्रॉडक्शन सब्सिडी देने का ऐलान किया था। यह रकम 1540 करोड़ रुपये की है। इससे चीनी मिलों को कुछ बकाया क्लियर करने में मदद मिलेगी। जून में सरकार ने 7000 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया ताकि सालभर में 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाया जा सके। दरअसल यह पैकेज वाइट शुगर का एक्स-मिल प्राइस कम से कम 29 रुपये प्रति किलो तय करने के रूप में था। सरकार ने यह भी कहा कि वह एथनॉल प्रॉडक्शन के लिए चीनी मिलों को लोन पर 1332 करोड़ रुपये की इंटरेस्ट रिलीफ देगी। केंद्र सरकार हर साल मिनिमम प्राइस तय करती है। इस भाव पर मिलों को गन्ना किसानों को पेमेंट करना होता है। कुछ राज्य इस कीमत से भी ऊंचा भाव तय करते हैं।

ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने कुल 8500 करोड़ रुपये से ज्यादा का राहत पैकेज घोषित किया है, लेकिन नेशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज (NFCSF) के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश पी नाइकनावरे ने कहा कि यह राहत कुल 4050 करोड़ रुपये से ज्यादा की नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टीज फेडरेशन के एमडी संजय खटाल ने कहा कि शुगर मिलें इस सीजन के लिए चीनी का भाव 32 रुपये किलो होने की उम्मीद कर रही थीं, लेकिन यह गिरकर 24 रुपये पर आ गई। उन्होंने कहा, 'अगर हमें 3200 रुपये प्रति क्विंटल का मिनिमम प्राइस मिलता तो पैकेज की जरूरत नहीं होती।'

देश की 524 चीनी मिलों में से 127 महाराष्ट्र और 119 उत्तर प्रदेश में हैं। महाराष्ट्र में अधिकतर चीनी मिलें को-ऑपरेटिव सेक्टर की हैं, वहीं यूपी में ज्यादा प्राइवेट मिलें हैं। महाराष्ट्र में Co 0238 के बजाय गन्ने की दूसरी किस्मों का उपयोग करने वाली सहकारी चीनी मिलों का दबदबा काफी ज्यादा है क्योंकि राजनीति के साथ उनका पुराना नाता रहा है। विट्ठलराव विखे पाटिल ने देश की पहली सहकारी चीनी मिल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 1951 में लगाई थी। उसके तीन साल बाद सरकार ने 12 और मिलों के लिए योजना की घोषणा की थी और समय के साथ पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनका महत्व बढ़ता गया, जहां शुगर इंडस्ट्री में मराठा समुदाय का दबदबा है।

ऐसी हर सहकारी मिल का सदस्यों के रूप में गन्ना किसानों का एक नेटवर्क होता है, लिहाजा ऐसी मिल को कंट्रोल करने का मतलब है कि एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाना। इन मिलों के बोर्ड्स के लिए चुनावों में अब भी काफी कड़ा मुकाबला होता है। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने कहा कि 1990 के दशक के मध्य तक हर शुगर फैक्टरी के लिए एक तय कृषि क्षेत्र हुआ करता था और उस एरिया से बाहर की कोइ भी चीनी मिल वहां के किसानों से गन्ना नहीं खरीद सकती थी। उन्होंने कहा, 'ऐसे में लोग डरते थे कि अगर वे शुगर फैक्टरी को कंट्रोल करने वाले कैंडिडेट (खासतौर से आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में) को वोट नहीं देंगे तो उनका गन्ना नहीं खरीदा जाएगा।'

पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित राज्य के कई नेता ऐसी सहकारी चीनी मिलों के या तो चेयरमैन या बोर्ड मेंबर रहे हैं। ऐसी अधिकतर सहकारी मिलें कांग्रेस के लोगों के नियंत्रण में रही हैं। इसमें उसे शरद पवार से भी काफी मदद मिली। पवार का होम टाउन बारामती पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। 1990 के दशक के आखिर में पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाकर जब कांग्रेस से किनारा किया तो अधिकतर सहकारी चीनी मिलों का नियंत्रण उनके लोगों के हाथ में चला गया। अब राज्य में दो तिहाई सहकारी चीनी मिलें एनसीपी के हाथों में हैं। कांग्रेस के पास 20 पर्सेंट और बीजेपी-शिवसेना के लोगों के नियंत्रण में बाकी चीनी मिलें हैं।

महाराष्ट्र के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनसीपी के दिलीप वलसे पाटिल का कहना है कि सहकारी चीनी मिलों का प्रभाव इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने इलाके में स्कूल आदि बनवाए हैं और खेतों में पानी का बेहतर ढंग से उपयोग करने वाली सिंचाई व्यवस्था बनाने में मदद की है। पाटिल ने कहा, 'पहले सहकारी मिलों का चुनावों में काफी महत्व था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि आज की पीढ़ी खेती-बाड़ी पर पहले की तरह निर्भर नहीं है। उसके पास दूसरे कई विकल्प हैं।' पाटिल पुणे जिले के अबगाव में एक सहकारा चाना मिल के चयरमन हैं। विधानसभा में इस इलाके का प्रतिनिधित्व वह 1990 से करते आ रहे हैं। वह NFCSF के प्रेसिडेंट भी हैं।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सभी सहकारी किसान संबंधित सहकारी चीनी मिल से जुड़ी पार्टी के सपोर्टर हों। मराठवाड़ा के नांदेड़ में एक सहकारी चीनी मिल के डायरेक्टर चव्हाण ने कहा, 'यह गलत धारणा है कि ये मिलें राजनीतिक संगठन हैं।' देशमुख का भी मानना है कि सहकारी मिलों की ताकत घट रही है। देशमुख का लोकमंगल ग्रुप सोलापुर और उस्मानाबाद में दो प्राइवेट चीनी मिलें चलाता है। उन्होंने कहा, 'अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप किसी सहकारी चीनी मिल के चेयरमैन हैं तो आप चुनाव जीत जाएंगे।'

सहकारी चीनी मिलों के प्रबंधन और वित्तीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। नाइकनावरे ने कहा, 'डायरेक्टर चूंकि किसान बिरादरी से आते हैं, लिहाजा उनकी सोच कॉरपोरेट सरीखी नहीं होती है। ऐसे में बिजनेस से जुड़े निर्णय करने में देर होती है और प्रायः गलत फैसले कर लिए जाते हैं।' देशमुख ने कहा कि राज्य में 40 के करीब पुरानी चीनी मिलों को रिवाइव करने के लिए 600-700 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकतर सहकारी क्षेत्र की हैं।

इसके अलावा समस्या ज्यादा शुगर मौजूद होने और कीमतों में गिरावट की भी है। 2017-18 (अक्टूबर से सितंबर) के दौरान ब्राजील के बाद दुनिया में चीनी के दूसरे बड़े उत्पादक भारत में 3.2 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान है, जो 2016-17 से 58 पर्सेंट ज्यादा है। इसके साथ ही ग्लोबल वाइट शुगर फ्यूचर्स में फरवरी 2017 से अब तक करीब 30 पर्सेंट की गिरावट आ चुकी है। वाइट शुगर फ्यूचर्स को फिजिकल वाइट शुगर की कीमतों का बेंचमार्क माना जाता है। इस लिहाज से यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र ने जो राहत पैकेज दिया है, उससे बीजेपी को किस तरह फायदा होता है। बीजेपी ने वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान और बाद में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पैठ बढ़ाई है। बीजेपी ने 2014 का आम चुनाव शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। 2019 का विधानसभा चुनाव भी दोनों अकेले लड़ सकती हैं।

राजनीतिक विश्लेषक नितिन बीरमल ने कहा कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में वह आबादी बीजेपी का सपोर्ट बेस है, जो खेती-बाड़ी पर निर्भर नहीं है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र जोंधले का मानना है कि गन्ना किसानों के मुद्दों पर फोकस कर बीजेपी अपनी पोजिशन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, 'केंद्र ने पैकेज वोटरों से कनेक्ट होने के लिए दिया। बीजेपी सहकारी मिलों के अध्यक्षों पर अंगुली उठा रही है। वह कह रही है कि किसानों की मदद तो वही कर रही है।'

इधर उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या मिलों से बकाया रकम नहीं मिल पाने से लेकर जाड़े के सीजन में कटाई में देरी तक फैली हुई है, जिसके चलते उन्हें गेहूं की खेती से समझौता करना पड़ता है। चीनी मिलें पर्चियां जारी करती हैं। अगर ये पर्चियां न हों तो किसान अपने गन्ने की कटाई कर उन्हें मिलों में नहीं ले जा सकते।

चीनी मिलों और किसानों के बीच का रिश्ता असहज किस्म का है। यूपी में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के 13500 करोड़ रुपये बकाया हैं। नकवी ने कहा, 'हाल में दिया गया राहत पैकेज केवल मिलों के लिए नहीं है। अगर मिलें दिवालिया हो जाएं तो सबसे ज्यादा परेशानी गन्ना किसानों को होगी। किसानों की तकदीर इन मिलों की सेहत से जुड़ी है।'

चीनी मिलों से अपना एरियर मिलने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति अधिकतर किसानों का गुस्सा कम हो जाएगा। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि चीनी मिलों पर गन्ना पहुंचाने के 14 दिनों के भीतर किसानों को पैसा दिलाया जाएगा। यह वादा भी कई दूसरे वादों की तरह अभी अधूरा है। बागपत जिले में बड़ौत के गन्ना किसान विजय भारद्वाज ने कहा, 'अधिकतर गन्ना किसान प्रधानमंत्री मोदीजी और मुख्यमंत्री योगीजी के समर्थक हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने दिल खोलकर पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन अब हम नाराज हैं और इसकी वजह भी है। सरकार को बेईमान मिल मालिकों की नकेल कसनी चाहिए और उनको हमारा बकाया देने पर मजबूर करना चाहिए।'

यह कहना तो अभी मुश्किल है कि 2019 के चुनाव में गन्ना किसान कितने प्रभावी रहेंगे, लेकिन यह साफ है कि राजनीतिक दल उन्हें नजरंदाज नहीं कर सकते हैं और आने वाले महीनों में बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार उन्हें और मनाने की कोशिश करेगी।

चीनी मिलों की सेहत से जुड़ी है गन्ना किसानों की तकदीर

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग के केंद्रीय सचिव एस के पटनायक ने शांतनु नंदन शर्मा से चीनी मिलों और किसानों के रिश्तों पर बातचीत की। पेश हैं इसके मुख्य अंशः

मिलों और किसानों पर

गन्ना किसानों की तकदीर चीनी मिलों की सेहत से जुड़ी है। दुनियाभर में चीनी के दाम में आने वाले उतार-चढ़ाव का असर किसानों पर पड़ता है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक होने के चलते ब्राजील एक तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुगर प्राइसेज तय करता है। लिहाजा हमारी चीनी मिलों के प्रदर्शन का मामला काफी अहम हो जाता है। चीनी मिलों के लिए हाल में घोषित पैकेज मुख्य रूप से मौजूदा समस्याओं को दूर करने के लिए है, जो गन्ना उत्पादन में हालिया उछाल के कारण पैदा हुई हैं। लिहाजा यह पैकेज अस्थायी किस्म का है और यह उत्पादन ज्यादा होने से बनी स्थिति से निपटने के लिए है। इस राहत पैकेज के बिना चीनी मिलों का चलना मुश्किल हो जाता और आगामी सीजन में वे गन्ना नहीं ले पातीं। किसानों को इससे दिक्कत होती। किसानों की भलाई के लिए भारत में चीनी का दाम 40 रुपये प्रति किलो होना चाहिए। अभी दाम इससे काफी नीचे है।

गन्ना, पानी और बिजली पर

गन्ने की खेती में पानी की काफी जरूरत पड़ती है, लिहाजा हमारे मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी थी कि ड्रिप इरिगेशन (पानी का किफायत से इस्तेमाल करने वाला माइक्रो इरिगेशन सिस्टम) को गन्ने की खेती वाले मौजूदा और नए इलाकों में अनिवार्य कर दें। महाराष्ट्र ने इसे लागू कर दिया है। हम गन्ने की ज्यादा खेती वाले दूसरे राज्यों को भी महाराष्ट्र मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सरकार गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में सोलर पावर के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने की कोशिश भी कर रही है और उन्हें ग्रिड से जोड़ रही है। आइडिया पानी की बरबादी कम से कम होने देने का है। किसान वॉटर पंपों का उपयोग उतना ही करेंगे, जितना जरूरी हो। जितनी ज्यादा बिजली वे बचाएंगे, उनसे उतनी ज्यादा बिजली ग्रिड खरीदेंगा और किसानों को इस तरह कुछ आमदनी होगी।

गन्ने का रकबा तेजी से बढ़ने पर

गन्ने की खेती का रकबा तेजी से बढ़ने में इसकी बहुत सफल रही किस्म CO 0238 का बड़ा योगदान है। इसकी उपज काफी ज्यादा है। इससे रिकवरी रेट यानी गन्ने में चीनी का प्रतिशत भी ज्यादा है। यह वेरायटी खासतौर से उत्तर प्रदेश में बहत लोकप्रिय हो गई है।